बिजली के दरों की समीक्षा किये जाने हेतू सुझाव

587. **श्री अजीत जोगी**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की दरों की समीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है; और

(ग) राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पी० वी० रंगैया नायडू**): (क) और (ख) जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्य-योजना को अपनाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति कि०वा० होनी चाहिए का प्रावधान किया गया था। राज्य बिजली बोर्डों के लिए निर्धारित किए गए तीन प्रतिशत का न्यनतम सांविधिक लाभ को प्राप्त करने के लिए अन्य उपायों के अलावा इसे आवश्यक समझा गया था।

(ग) उपलब्ध सूचनानुसार 13 राज्यों तथा 1 केन्द्रशासित क्षेत्र द्वारा 50 पैसे प्रति कि०वा० की न्यूनतम कृषि टैरिफ लागू कर दी गई है।

असम में गैस-आधारित "अंगूरी" विद्युत संयंत्र

588. **श्री अजोत जोगी**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में स्थापित किये जाने वाला प्रस्तावित गैस-आधारित "अंगूरी" विद्यूत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पी.वी. रंगैया नायडू**): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1991 में 408.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राज्य क्षेत्र के क्रियान्वयन हेतु असम में अंमगड़ी में 360 से० व० क्षमता वाले गैस आधारित संयक्त साईकिल विद्यत संयंत्र के प्रतिष्ठापन हेतु स्कीम को मंजूर किया गया था। चूंकि वित्त व्यवस्था को पुष्टि न हो सकी इसलिए इस परि-योजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने अब इस परि-योजना का निष्पादन निजी क्षेत्र द्वारा करवाने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए 10-6-1993 को असम राज्य बिजली बोर्ड और मैसर्स एन.ई. आई. इन्क. यू. एस.ए. के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना को पूरी करने की अवधि का अनुमान सभी औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने और संयंत्र और उपस्कर के लिए सप्लाई आर्डर दे दिए जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

589. **श्री अजीत जोगी**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन इसकी मांग-के-अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को बिजली की आवश्यकता को किन-किन राज्यों से पूरा किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्य में बिजली की कमी के वर्ष 1994-95 तक बने रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विद्युत मत्रालय में राज्य मत्री श्री पी.वी. रंगया नायडू): (क) अप्रैल, 1993 की अवधि के दौरान मध्य

प्रदेश राज्य में वास्तविक विद्युत आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(सभी आंकड़े मि.यू. निवल में)

	अप्रैल–अक्तूबर, 1993
आवश्यकता	12355
उपलब्धता	11765
कमी	590
(%)	(4.8)

वर्तमान में इस राज्य में उद्योगों पर कोई भी विद्युत कटौती लागू नहीं है तथा कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन लगभग 20 घंटे (औसत) के लिए बिजली दी जा रही है।

(ख) इसके अपने उत्पादन के अलावा मध्य प्रदेश केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से अपना और तथा पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्रों के केन्द्रों से अनाबंटित 15% से सहायता प्राप्त कर रहा है। इस समय, मध्य प्रदेश बालको, आरएसपी, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली के लिए 83 मे.वा. के विशिष्ट आबंटन को लेखे में लेने के पश्चात् केन्द्रीय क्षेत्र के अनाबंटित उत्पादन में से 40% आबंटित किया जाता है। मध्य प्रदेश ने निकटवर्ती राज्यों प्रणालियों से दिन प्रतिदिन उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सहायता भी प्राप्त की है। अप्रैल-अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र और निकटवर्ती प्रणालियों के केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से निमत मात्रा की अपेक्षा वास्तविक आहरण के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :—

(सभी आंकड़े जल मि. यू. में)

	अप्रैल–अक्तूबर, 1793	
	नियत मात्रा	वास्तविक आहरण
पश्चिमी क्षेत्र में		
केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्र	4734.2	5387.5
राजस्थान	---	159.1
उत्तरी ग्रिड	—	16.5

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आठवीं योजना विद्युत कार्यक्रम के अनुसार 1994–95 के अन्त तक मध्य प्रदेश में प्रत्याशित शिखर कमी तथा ऊर्जा कमी 22.2% तथा 9.6% होगी।

(घ) मध्य प्रदेश में विद्युत कमी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जोकि ये है–नव उत्पादन क्षमता के प्रचालन में तेजी लाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन को सुधारना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन तथा कमी वाले क्षेत्रों को बचत वाले क्षेत्रों से ऊर्जा अन्तरित करना। समय-समय पर पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों के अनाबंटित उत्पादन में सहायता उपलब्ध करवाना। आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 2351 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह राज्य केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं तथा पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जा रही संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं से अपना शेयर प्राप्त करेगा।

Recommendatoions of K. P. Rao Committee

590. SHRI KAMAL MORARKA: Will the MINISTER OF POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the K. P. Rao Committee has recommended fiscal incentives for promoting bulk energy conservation;

(b) if so, the details of the recommendations; and

(c) whether Government have considered the recommendations; and mendations;

(d) if so, the decision taken thereon? X

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (d) The K. P. Rao Committee was set up to suggest principles and normative parameters for working out